15.28 HRS.

UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1968*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69."

The motion was adopted.

SHRI K.C. PANT: I introduce† the Bill.

I beg to move†:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Mr. Shiv Charan Lal.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur): No discussion now.

MR. CHAIRMAN: He can speak with the permission of the Chair.

It was granted by the Deputy Speaker. He had given previous notice of this.

MR. SHIV CHARAN LAL: The Hon. Member may not take much time because we are pressed for time.

श्री शिवचरण लाल (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं खाली दो मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। गृह मंत्री हमारे सामने हैं। जिला आगरा में थाना फिरोजाबाद ग्राम तोतलपुर और सोफीपुर में वहां की मौजूदा पुलिस ने निषादों के साथ ऐसा जुल्म ढाया है जैसा कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद अंग्रेजों की पुलिस ने भी वैसा अत्याचार न किया होगा। 36 घंटों तक बेरहमी के साथ 11 मकानों की लूट की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यहार और भ्रष्टाचार तक किया गया, पुख्ता मकानों को धरा शायी किया गया। लाखों रुपयों की सम्पत्ति को लूटा और बरबाद किया गया, हरी भरी फसलों को उजाड़ कर तहस नहस किया गया। जो कृषि यन्त्र सिंचाई के थे पम्पिंग सेट और मशीनें उन को नष्ट किया गया। बैलों की कुट्टी की मशीनों को भी नहीं छोड़ा गया। 1100 मन गल्ला किसानोंका पुलिस ने लूटा और आम रास्ते पर 20 रुपये मन के हिसाब से बेच दिया और उधार तक दिया। सैकड़ों रुपये तोले के सोने के जेवरात और चांदी की चीजें भी पुलिस लूट कर ले गई। जो मशीन चलाने वाली लकड़ियां थीं उन को भी खोद खोद कर लूट ले गई। जीवनोपयोगी वस्तुयें जैसे चाकी चूल्हे, खिड़कियां, किवाड़े तक उखाड़ कर ले गई। उत्तर प्रदेश में पुलिस की यह बर्बरता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। एक कवि का शेर सुनिये :—

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, Dated 27-8-68.
†Introduced/moved with the recommendation of the President.

"काम की उल्टी ग्राज है बोली,
मुख से ग्रहिंसा हाथ से गोली।

नरम जबां ग्रौर पत्थर दिल है,
मुख से करधा हाथ में मिल है।
जनवादी बस नाम हुग्रा है,
तानाशाही काम हुग्रा है।"

सैकड़ों रुपयों के पुराने चांदी के सिक्के ग्रौर हजारों रुपयों के नोट पुलिस लूट कर लें गई। इस के खिलाफ 12 तारिख से 71 व्यक्ति ग्रामरण अनशन कर रहे थे। कल हमारे ग्रध्यक्ष श्री जोशी ने ग्रौर श्री शुक्ल ने ग्राश्वाशन दिया कि इस की न्यायिक जांच करवाई जायेगी ग्रौर कहा कि ग्रनशन तुड़वा दिया जाये तो ग्रच्छा है। मैं मांग करता हूं कि इस काण्ड की न्यायिक जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज द्वारा हो ग्रौर इस काण्ड के लिये जिम्मेदार जो पुलिस ग्रधिकारी, एस पी, ग्रादि हों उन को तुरन्त निलम्बित किया जाये या उन को ग्रागरे से हटाया जाये। पीड़ित परिवार के लोगों की, जिन की सम्पत्ति की लूट हुई है, सम्पत्ति वापस दिलाई जाये ग्रौर उन की जो क्षति हुई है उस के लिये उन को तत्काल मुग्रावजा दिया जाये। साथ ही पीड़ित परिवार वालों के विरुद्ध जो ग्रभियोग हैं उन को वापस लिया जाये। हमारे जिला ग्रागरा में इस तरह की घटना हुई है।

इसी तरह से छाता में हुग्रा, बलिया में हुग्रा, गोंडा में हुग्रा। वहां पर भी पुलिस के जरिये होने वाले जुल्म सीमा पार कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रगर इस तरह से मैं ग्रपने गृह मंत्री से ग्रपनी बात नहीं कह सकता तो फिर क्या किसी दूसरी जगह जा कर ग्रौर दूसरी सभा में ग्रपनी बात कहूंगा? इस तरह चीजों से ग्राज जनतन्त्र यहां पर चलाया जा रहा है, डुबाया जा रहा है ग्रौर पुलिस की बर्बरता बढ़ती चली जा रही है।

इसी तरह से हरिजनों पर ग्रत्याचार हो रहा है। एक ग्रौर दर्ख्वास्त मैंने उन को दी है ग्रौर कहा है कि ग्रागरा, ग्रालिगड़, बुलन्दशहर ग्रौर गोंडा में हरिजनों पर जो ग्रत्याचार हुग्रा है उस की जांच की जानी चाहिये। साथ ही जो भी ग्रधिकारी दोषी पाये जायें उन को बर्खास्त किया जाये। ग्रगर ग्रल्पसंख्यकों की बात मैं यहां नहीं कहूंगा तो फिर कहां कहूंगा। मेरा ग्रपना निवेदन ग्राप से है कि इस तरह की घटानाग्रों से यह जाहिर होता है कि यहां पर जनतन्त्र नहीं है, हिटलर का दरबार है। ग्रगर इस तरह से पुलिस का जुल्म बढ़ता चला गया तो हमारा यह जनतन्त्र गड्ढे में चला जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि:

ख़ुशी से चेहरा कोई दर्कसन्दा नहीं मिलता
जवां बेकार फिरते हैं, कोई धन्धा नहीं मिलता
मरने को जो तैयार हो उसे फन्दा नहीं मिलता
मर भी जाये तो कफन के वास्ते चन्दा नहीं मिलता।
कहां से खैर हो, दौरे जफा बदले तो क्या बदले?
वही कल हैं वही पुर्जे, फिजा बदले तो क्या बदले?
वही हिकमत, वही नुस्खा, दवा बदले तो क्या बदले?
वही मकसद, वही तेवर, ग्रदा बदले तो क्या बदले?
हमें नफरत न थी ग्रंग्रेज की कोम, सूरत से
हमें जो कुछ भी नफरत थी उस के ग्रन्दाजे हुकूमत से
ग्राज ग्रपनों की हुकूमत रहमत हो नहीं सकती

[श्री शिवचरण लाल]

तो अपनों की सूरत से भी मोहब्बत हो नहीं सकती।

आखीर में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहां के लोगों से अनशन छुड़वाया गया है तब जो भी मांगें मैंने रक्खी हैं उन को पूरा कर के उन लोगों को मुआवजा दिया जाये। उन के जो मकान नष्ट-भ्रष्ट किये गये हैं वह उन को फिर से दिये जायें और जो उन की सम्पत्ति लूटी गई है वह उन्हें वापस की जाये। मैं ने तोतलपुर और सोफीपुर की पूरी घटना आप के सामने रक्खी है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप तुरन्त गौर करें और गौर करके सम्बन्धित अधिकारियों का तबादला करें। जिन्होंने अत्याचार किये हैं निहत्थी जनता पर, छात्रों पर, महिलाओं पर उनका आप तबादला करें और उनको आप सजा दें।

श्री शिव नारायण : ट्यूबवैल्ज के बारे में जो डिमांड की गई है वह बड़ी जैनुइन डिमांड है। जो उन पर टैक्स बढ़ाया गया है, वह क्यों बढ़ाया गया है? क्यों उनके लिए बिजली महंगी की गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस के बारे में पोजिशन को क्लीयर करें।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : हरिजनों पर जो भी अत्याचार हुए हैं और चाहे कहीं भी हुए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हुए हों या इस देश के किसी और कोने में, उसके खिलाफ इस सदन में जरूर आवाज़ उठनी चाहिये और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर यहां इशारा किया है, इसको सामने लाए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में जितना रोष उनको है, उससे कम रोष हमको नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस में कोई चीज निकली, ज्यादती वाली बात निकली तो जरूर वाजिब सम्बन्धित लोगों को दंड दिया जाएगा। मैं इसके मैरिट्स में नहीं जा सकता हूं क्योंकि आगरा के मामले में और गोंडे के मामले में ज्यूडिशल इनक्वायरी चल रही है। इस वास्ते मैं यह नहीं चाहूंगा कि मैं इसके मेरिट्स पर कुछ कहूं और न ही माननीय सदस्य मुझे कुछ कहने के लिए विवश करेंगे। हम लोगों को पहले इस बात का पता लगाना है कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता मालूम होने पर जो दोषी हैं उनको दंड देना सरकार का कर्त्तव्य होगा।

बनर्जी साहब ने एक प्रश्न पूछा था। वह इस वक्त यहां से चले गए हैं। उसके बारे में कुछ सूचना मेरे पास आई है और उसको आपकी आज्ञा से मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में पांच लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनकी तनख्वाह 509 रुपये महीने तक है, चार करोड़ सालाना खर्च करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके महंगई भत्ते की दर को केन्द्रीय कर्मचारियों की दर के बराबर लाया है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि पिछले तीन बरसों में पांच ऐसी बढ़ोतरियां महंगाई भत्ते में उत्तर प्रदेश की सरकार ने की हैं।

अब मैं आप की इजाजत से श्री शिव नारायण ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके जानकारी सदन को मैं दूं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं सदन को देने की चेष्टा करता हूं। लेकिन अगर दस पंद्रह मिनट का समय हो और मुझ से आशा की जाए कि मैं सारी बहस का सिलसिले बार उत्तर दूं तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर मुद्दे पर मैं पूरी तफ़सील से नहीं जा सकता

हूं। यह एक ऐसा मामला है कि जिस को मैं पूरी तरह से समझाऊं तो काफी समय लग जाएगा। मेरे पास यह तीन पेज का नोट ग्राया है। मैं सारे नोट को नहीं पढ़ता हूं। इस की कुछ मुख्य बातें ही मैं ग्रापके सामने रखता हूं। पहले ऐसा होता था कि एक मिनिमम रेट होता था प्राइवेट पम्प्स के लिए और वह नब्बे रुपये हर हार्स पावर के पीछे होता था ग्रौर इस मिनिमम गारंटी के ऊपर ग्रगर कोई बिजली लेता था तो उसको ग्रधिक पैसा देना पड़ता था। ग्रब सारे प्रदेश में एक ही दर लागू कर दी गई है ग्रौर उस में फिक्स्ड जार्ज है ए सी ग्रौर डी सी के लिए। ग्रब 96 रुपये कर दिया गया है। इसका ग्रर्थ यह होता है कि 12.32 पैसे फी यूनिट लगते हैं ग्रगर ट्यूबवैल या पम्पिंग सैट को तीन हजार घंटे सालाना चलाया जाए। ग्रगर कम चलाया जाएगा तो दर ग्रधिक हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि जहां भी प्राइवेट ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो ग्रौर जब उनका प्रयोग ज्यादा होगा तो यह जो दर इस वक्त ज्यादा लगती है वह दर ग्रपने ग्राप ठीक हो जाएगी। ग्रगर तीन हज़ार घंटे प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ग्राज जितने दाम लगते हैं बिजली के करीब करीब उतने ही तब लगेंगे........

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : (बागपत) : ग्राप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं.....

श्री शिव नारायण : ग्राप ने ग्राठ रुपये फी हार्स पावर बटाया है। इसका मतलब यह हुग्रा कि साढ़े सात हार्स पावर पर ग्रापने साठ रुपये बढ़ा दिये हैं। पहले का जो एग्रीमेंट था वह साढ़े सात हार्स पावर पर 675 रुपये का था......

SHRI K. C. PANT: May I explain it in a nutshell? Previously there was a minimum rate. Now the minimum has been raised. If there is a better utilisation of the private tube-wells, the rate would be about the same. (*Interruption*).

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : ग्राप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं.....

श्री कृष्ण चन्द पन्त : इस मसले को ग्राप सलाहकार समिति में भी उठा सकते हैं......

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : पालियामेंट में ग्राप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : बड़ी मुश्किल है। सूचना जो मेरे पास ग्राई है वही तो मैं दे सकता हूं। ग्रापको ग्रगर संतोष नहीं होता है तो ग्राप मुझे पत्र लिखें ग्रौर मैं जानकारी प्राप्त करुंगा। सलाहकार समिति में भी ग्राप इसको लायें ग्रौर जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : यहीं पर ग्राप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं ग्रौर मैं ग्रापको बताता हूं कि....

श्री कृष्ण चन्द पन्त : ग्राप क्या बता सकते हैं कि कौन सी गलत बात है?

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : ग्राप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : एक घंटा ग्रौर दे दें तो एक घंटा ग्रौर बहस कर लीजिये।

श्री शारदा नन्द : बिहार बजट पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि केन्द्र ने यह तय किया है कि बिहार के किसानों पर ग्रौर हिन्दुस्तान भर के किसानों पर बिजली की दर बढ़ाई नहीं जाएगी ग्रौर बिहार के किसानों से बारह पैसे यूनिट से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह चीज़ बिहार में ही लागू होगी या उत्तर प्रदेश में भी इसको ग्राप लागू करेंगे।

MR. CHAIRMAN: He cannot say now. He requires notice for all these questions. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the clauses to the vote.

The question is:

"That clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT: I move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.48 HRS.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF UTTAR PRADESH

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की बाद की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित 25 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरंतर लागू रखने का अनुमोदन करती है"।

सभापति महोदय, यह सचमुच में ही हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि इस तरह की चीज़ हम को लानी पड़ रही है और वह भी इस देश के सब से बड़े प्रदेश के लिए। लेकिन वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन से विवश हो कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा और उसकी अवधि को बढ़ाना पड़ा? इन परिस्थितियों से यह माननीय सदन अच्छी तरह से अवगत है और मुझे उसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस तरह से वहां पर पिछले आम चुनाव के बाद राजनीतिक घटनायें और दुर्घटनायें हुई और उसके बाद किस तरह से राजनीतिक अवसरवादिता का वहां पर खेल खेला गया, इस सब से माननीय सदस्य अवगत हैं। जब यह देखा गया कि संविधान के अन्तर्गत वहां का प्रशासन चलना असम्भव हो गया है तब राज्यपाल ने इस बात की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय से की कि वहां का जो शासन है उसे खत्म करके राष्ट्रपति जी का शासन वहां लागू कर दिया जाए तथा मध्यावधि चुनाव कराये जायें। इस सिफारिश के पहले यह आशा की जाती थी कि अगर वहां पर विधान सभा को थोड़ा स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद इस बात का प्रयत्न किया जाए कि किसी तरह से वहां जिम्मेदार सरकार कायम हो सके तो की जाए और इस तरह की सिफारिश भी राज्यपाल महोदय की तरफ से की गई थी। हम लोगों के लिए—और मैं समझता हूं कि सदन के सब माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे—यह दुख की बात है कि वहां पर इस तरह की कोई जिम्मेदार सरकार नहीं बन सकी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : इस का मौका ही नहीं दिया गया।